DISCUSSION UNDER RULE 176

Report of the Working Group on Autonomy for Akashvani and Doordarshan

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Now, discussion under rule 176,..(*Interruption by Shri Sitaram Kesri*).... Mr. Kesri, please take your seat.

Hon. Members will note that there is **a large number of Members who want** to speak. I also am aware that you may desire or you will desire that the Minister must also reply. This discussion was to start at 3.30 p.m., but actually we are one hour and 10 minutes late. Anyway, I would request the co-operation of the various parties, that those who want to participate will limit their observations to not more than seven minutes. Otherwise I cannot accommodate all the Members. So I would request you that you will please keep to the time. Now I call on Shri Shrikant Verma to start the discussion.

SHRI SHRIKANT VERMA (Madhya Pradesh): Sir, as the initiator I should be given more time.

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): There are 20 persons and there are two hours. I am prepared to sit here up to 6.30 p.m.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): What has happened to our request for a discussion of External Affairs tomorrow? Nothing? No information?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The hon. Member will please listen. It was laid here but the Government has not agreed . So, no extension can be made of this House. So, I would only request you to co-operate, and whatever you are going to speak, I think you would like in all aspects that Mr. Advani should reply. Otherwise the discussion cannot be completed. Only the Members will speak and the Minister will not able to speak.

DR. V. P. DUTT (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, this subject deals with one of the most important, one of the most sensitive and one of the most vital sources of information media in the country and to expect that on a Report which has taken many months to be prepared after due deliberation and which, if implemented, will create a new system of information for this country we should limit our comments only to five or seven minutes cnly means that we should not be able to say anything. All we can do then is we get up and say, we like the Report or we do not like the Report and sit down. Therefore, I would like the guidance of the Leader of the House because it is his Ministry also. Some way should be found by which such a serious subject can be discussed seriously.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I have understood what you want to say, but anyway there are various limitations of time. I ask Mr. Shrikant Varma to proceed.

श्री श्रीकान्त वर्मा : उप-सभाध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू ने 1948 मे आकाशवाणी के लिए एक स्वायत्त ढांचे की कल्पना की थी और कहा था कि अच्छा होगा कि बी०बी०सी० के ढंग का कोई कारपोरेशन आकाशवाणी के लिए बने । लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह रातों-रात नहीं हो सकता क्योंकि स्वतंत्रता आसमान से नहीं गिरती है, स्वतंत्रता मनुष्य की अंतरात्मा और विवेक मे जन्म लेती है और एक लम्बी यात्रा पूरी करती है । इसलिए अगर हम 50 वर्षों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए किसी स्वायत्त संस्था

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

को रचना नहीं हो सकती इसके लिए पिछली सरकार को दोष देने की आवश्यकता नहीं और अगर आजनई सरकार ने आकाशवाणी और दूर-दर्शन के लिए एक परिकल्प की है तो इसके लिए उसे बधाई देने की आवश्यकता नही ।

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI (Delhi): Better late than never.

श्रीश्रीकन्त वर्मा : क्योंकि हमारे समाज के दबाव से यह संस्थाा पदा हुई हैऔर पैदा होने जा रही है ।समाज की मांग के अनुसार ही स्वतंत्रता का विकास होता है और उसके अनुसार उसकी परिभाषा होती है । लेकिन जैसा कि वर्गीस कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूपसे का गया है कि स्वायत्तता क्या है, इसको भी समझ लेना होगा ।

उपसभाध्यक्ष महोयद, स्वायत्तता का अर्थ केवल सरकारी हस्तक्षेप, से मुक्ति नही है बल्कि अपन होन का अहसास भी है और जो शासन आकाशवाणी और दूर-दर्शन के लिए एक स्वायत्त संस्था कल्पना करता है, फिर उसे ऐसी परिस्थितियों की भी रचना करनी होगी जिनमें कि यह संस्था सच्चे अर्थों में स्वायत्त हो सके । वास्तविकता तो यह हैकि स्वतंत्रता कोई भौतिक स्थिति मात्र नही होती बल्कि वह एक मानसिक बनावट की उपज होती है ।

श्रीमान, ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन का लाइसेंस वहां का पोस्ट-मास्टर जनरल रद्द कर सकता है । यह उसका नियम है लेकिन आज तक इतने वर्षो में कभी भी यह नौबत नहीं आईजब कि पोस्ट-मास्टर जनरल को लाइसेंस रद्द करने अथवा चेतावनी देने की जरुरत महसूस हुई हो । आखिर इसका कारण क्या है ? इसका कारण है ब्रिटिश समाज का वह ढांचा जिसकी उपज हैं ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन और उसके साथ वहां की सरकार का रिश्ता । दोनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बराबर कायम रहा । वर्गीस कमेटी ने जिस स्वायत्तता की कल्पना की है वह तो फिर भी बहुत है, ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन को तो वह भी प्राप्त नहीं है, फिर बी० बी० सी० आज हमसे कहीं अधिक स्वायत्त है, केवल समाचारों के मामलों में ही नही और भी मामलों में । इसलिए जैसा समाज होगा वैसा ही उसका रेडियो होगा, वैसी ही उसकी वाणी होगी । यह कहना सही होगा कि जैसी वाणी होगी समाज की वैसी ही उसकी आकाशवाणी होगी । उपसभापति जी, वाणी की स्वतंत्रता तो हमारे संविधान में ही निहित है और उस सविधान में निहित अर्थ को ही श्री वर्गीस कमेटी स्पष्ट करना चाहती है और उसके लिये स्वायत्त ढांचा रचना चाहती है । लेकिन मुझे उसमें कुछ खतरे नजर आते हैं और वे खतरे इतने साफ है कि उन पर पहले ही विचार कर लेना आवश्यक होगा । मसलन, उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए एक ट्रस्ट की कल्पना की है । आखिरकार यह ट्रस्ट क्या है ? समिति कहती है कि इस ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति लोकपाल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा तैयार की गई सूची से होगी और उसे प्रधान मंत्री के पास भेजा जाएगा । संभवतः सूचना और प्रसारण मंत्री को ज्ञात होगा कि उन्हीं के आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों ने एक चिट्ठी प्रसारित की है, जिसमें इसका विरोध किया गया है । इस विरोध का कारण यह है कि कर्मचारी यह महसूस करते है कि यह पूरी स्वायत्ता नहीं है । अगर स्वायत्ता होनी है तो पूरी स्वायत्ता होनी चाहिये । प्रधान मंत्री के पास यह सूची भेजने की क्या आवश्यकता है ? प्रधान मंत्री कोई भी हो, लेकिन अन्ततः एक राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक व्यक्ति की अपनी रुचियां हो सकती हैं । उस सूची में उनके अपने मनपसंद नाम भी हो सकते है और उस

को राष्ट्रपति के पास भेजकर एक ऐसी तालिका तैयार करा सकते हैं जो ऊपरी तौर पर देखने में स्वतंत्र न्यास लग सकता है लेकिन वास्तव में एक सरकारी एजेंसी होगी। यह एक ज्यादा सुविधाजनक स्थिति होगी। यह अधिक आसान होगा सरकार के लिये कि उसके हाथ भी न जले और काम भी हो जाए। काजल की कोठरी में भी न जाए, दाग भी न लगे और काम भी बन जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी इस संबंध में कोई बिल आए या विधेयक आए तो उसको रद्द कर देना चाहिए। सरकार को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं करनी चाहिये कि प्रधान मंत्री इस सूची पर विचार करें। यह सूची सीधे राष्ट्रपति के पास जानी चाहिये। राष्ट्रपति ही उनमें से नाम तय करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि आकाशवाणी या वाणी एक खतरनाक माध्यम भी है और एक महान संभावनाओं वाला माध्यम भी है। इसमें दोनों ही चीजें हैं। अगर हम उसका सदुपयोग करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। हम अपने आप को ज्यादा सभ्य समाज के रूप मे पेश कर सकते हैं और अगर हम उसका दुरुपयोग करना चाहेंगे तो उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इस बारे में मैं उदाहरण नहीं देना चाहता क्योंकि पीछे उदाहरण दिये जाते रहे हैं। इसी सदन मे बार-बार उदाहरण दिये गए हैं। मै भी पिछले एक वर्ष का उदाहरण देना चाहता हू।

उपसभाध्यक्ष जी, हर रोज आकाशवाणी 242 बुलेटिन विभिन्न भाषाओं मे प्रसारित करती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं लेकिन आकाशवाणी प्रति दिन 33 घंटे 19 मिनट समाचार प्रसारित करती है। इसका हिसाब लगाकर मैंने देखा है कि प्रति मिनट 100 शब्द की रफ्तार से लगभग 2 लाख शब्द आकाशवाणी प्रसारित करती है समाचारों के अंतर्गत। इस हिसाब से सोचिए कि एक वर्ष में कितने शब्द प्रसारित किये गये और उन शब्दों का क्या असर हुआ है। मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूं वह यह है कि आकाशवाणी जबतक विश्वसनीय है या दूरदर्शन या कोई भी संचार माध्यम विश्वसनीय है तब तक उन्हीं शब्दों का अर्थ है लेकिन जिस दिन शब्द विश्वसनीय नहीं रह जाते उसी दिन वे बेमानी शब्द हो जाते हैं, वे खो जाते है। इसका एक उदाहरण यह है कि पिछले साल श्रीमती इन्दिरा गांधी की चरित्र हत्या या विरोध कह लीजिए, अगर यह शब्द आपको पसंद न हों तो, उनका विरोध लगभग 73 लाख शब्दों ने पिछले एक साल मे आकाशवाणी ने किया। लेकिन क्या इससे आन्ध्र में, कर्नाटक मे, आजमगढ़ के चुनावों मे असर पड़ा? मैं कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि 73 लाख शब्द श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरोध मे बोले गये, शायद ही कोई एक अच्छा शब्द बोला गया होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका चुनावों पर कोई असर पड़ा? कोई असर नही पड़ा। हम लोगों ने भी जब हमारी सरकार थी, हमारी आकाशवाणी थी उस समय श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई के बारे में बहुत सी गलत बातें कही होंगी लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। मैं किसी का पक्ष नही ले रहा हूं क्योंकि यह टैक्निकल विषय है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आकाशवाणी आज से नही बल्कि कई सालों से इसी प्रकार से चल रही है। इसमें दोष श्री विद्याचरण शुक्ल का भी है और दोष श्री आडवाणी का भी है। अगर श्री विद्या चरण शुक्ल का शासन काल कलियुग के नाम से याद रखा जाएगा तो श्री आडवाणी का काल सतयुग के नाम से याद नही रखा जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा दोष श्री शुक्ल का है तो श्री आडवाणी का भी कम नहीं होगा। मै समझता हूं कि वास्तव में दोष मध्यम वर्ग के उन कर्मचारियों का है जो मानसिक रूप से ग्रस्त है और जो आकाशवाणी और दूरदर्शन को चला रहे हैं। वे भयानक मानसिक दासता के रोग

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

से ग्रस्त हैं। वे लोग राजा से भी अधिक राजा के प्रति वफादार रहना चाहते हैं और राजा को नंगा नहीं देखना चाहते हैं और अगर उसको नंगा देखते हैं तो उसको लबादा ओढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों ने इन माध्यमों की विश्वसनीयता को अपने माध्यम से और संचार साधनों के माध्यम से समाप्त कर दिया है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि पिछले एक साल में कितनी ही बार यह कहा गया है कि आकाशवाणी में 60 प्रतिशत समाचार विरोधी पार्टियों के बारे में प्रसारित हुए हैं। केवल 40 प्रतिशत समाचार जनता पार्टी के बारे में प्रसारित हुए। असल में सवाल यह नहीं है कि किसको कितना समय दिया गया। सवाल यह है कि किस के बारे में क्या कहा जाता है और यही बात महत्वपूर्ण होती है। आकाशवाणी पहले जो कुछ कहती थी, अब भी वही कहती है। स्थिति यह है कि नाम बदले हैं, कफन बदले हैं, लेकिन मुर्दा नही बदला है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्गीज कमेटी की रिपोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें पैदा नहीं हुई हैं क्योंकि उसकी अन्तर्रात्मा को बदलने के लिए क्या किया जाए, इस बारे में इस कमेटी को रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। केवलमात्र आकाशवाणी के 10-20 या 50 कर्मचारियों को बदल देने से समाज नहीं बदल जाता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सम्बन्ध में मानसिक रूप से एक नया ढांचा तैयार किया जाए। इतना होते हुए भी मैं वर्गीज कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत करता हूं क्योंकि अपनी सीमाओं के बावजूद उसने आकाशवाणी की विश्वसनीयता को प्रतिष्ठित कराने की कोशिश की है। उसने अपने सामने एक आदर्श रखा है कि आकाशवाणी और दूर-दर्शन को सरकारी और अर्द्ध-सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। मैं मानता हूं कि समाज को बदलने के लिए कुछ खपती, पागल, आदर्शवादी कहलाने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। जिस रोज हमारे सामने आदर्शवाद का सिद्धान्त नहीं रहेगा उस रोज समाज बर्बर हो जाएगा।

इसके साथ-साथ इसके दूसरे पहलू को भी देखने की जरूरत है। केवलमात्र आदर्श को देखने से ही काम नहीं चलता है। हमें यथार्थ को भी देखना पड़ता है। वे लोग ही इन बातों का विरोध करते हैं जो अब तक विश्वसनीयता का विरोध करते रहे हैं। हमारे देश का जो राजनैतिक ढांचा है वह इन चीजों को बर्दाश्त करेगा, इसको अभी हमें देखना है। मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी—मैं किसी एक पार्टी की बात नही कहता—यह नहीं चाहेगी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन उसके नियंत्रण से निकल जायें। यह तो हर पार्टी के नेताओं को अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना चाहिए कि वास्तव में उनकी इस बारे में क्या इच्छा है। आपको स्वयं चार-पांच महीने के बाद मालूम हो जाएगा कि इस बारे में आप क्या चाहते हैं। जब सरकार का इस बारे में फैसला आ जाएगा तभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। केवल मात्र रिपोर्ट प्रकाशित करने से काम नहीं चलता है। रिपोर्ट प्रकाशित करना तो आसान है, लेकिन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार करना बहुत कठिन है। इस रिपोर्ट में जो सबसे दुःखद बात रखी गई है वह बोर्ड आफ ट्रस्टीज की नियुक्ति के सम्बन्ध में रखी गई है। बोर्ड आफ ट्रस्टीज की नियुक्ति कैसे हो, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जब भी बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन हो तो सब बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा आपने प्रैस आयोग के सम्बन्ध में कुछ लोगों की नियुक्तियां कर दीं। वैसा नही होना चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग हों, जो अपने क्षेत्र के चुने हुए लोग हों, जिनका ताल्लुक विश्वविद्यालयों, अध्यापकों, ट्रेड यूनियनों, छात्र संघों, अकादमियों, लेखकों की संस्थाओं आदि से हो, उन सब को बोर्ड आफ ट्रस्टीज में लिया जाना चाहिए। वे लोग इस देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों को समझेंगे।

5 P.M. दूसरे, लोग राजनीति का समझ सकते हैं लेकिन देश की मानसिक आजादी को नहीं समझ सकते। यह आकस्मिक नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले 20-25 सालों से जब जनता पार्टी विपक्ष में थी ; तब भी और आज जब हम विपक्ष में हैं, तब भी केवल आकाशवाणी का समाचार विभाग ही विवाद का विषय बनता रहा है । इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा एक चीज हावी है और वह है राजनीति । हम समझते है कि केवल राजनीति ही एक ऐसी चीज है . . .

Time bell rings

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे दिमाग पर यह बात हावी है कि केवल राजनीति ही सब कुछ है । हम दूसरी चीजों की ओर इस निगाह से नही देखते । हम किसी भी अन्य क्षेत्र की ओर निगाह करने में संकोच अनुभव करते हैं । लेकिन समाज एक सम्पूर्ण चीज होती है । आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकारों की मांग बिलकुल न्यायोचित है कि इसमें अवकाश प्राप्त राजनैतिक नेताओं को ट्रस्टी न बनाया जाय, बल्कि विभिन्न संगठनों, जिनका ताल्लुक संस्कृति, समाज और जीवन के तमाम क्षेत्रों से हो, उनके आये हुए लोगों के प्रतिनिधियों को इसका प्रतिनिधि बनाया जाए और सेवा में विशेषज्ञों को ज्यादा महत्व दिया जाए । महोदय, सबसे बड़ा खतरा यह है कि जो भी ट्रस्टी होंगे वे सुपर बासेज हो सकते है । हम जानते हैं कि किस तरह से आज भी भारत सरकार में सुपर बासेज बैठे हुए है । इस स्वायत्त संगठन में भी इसका खतरा है क्योंकि वर्गीस कमेटी ने सेन्ट्रल एक्जीक्यूटिव बोर्ड और ट्रस्टियों के बीच क्या रिश्ता होगा इसको अस्पष्ट रखा है, इसको साफ नहीं किया है । कहीं कामों का डुप्लीकेशन हो सकता है और कितना एक्जीक्यूटिव बोर्ड स्वतंत्र होगा निर्णयों के लिये और कहां तक ट्रस्टियों के निर्णयों उन पर हावी नहीं होंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है । इसलिये ट्रस्टी जो हैं वे सुपर बास बन जायेंगे, इसका पूरा अंदेशा है । इसको रोकने के लिये यह आवश्यक है कि राजनीति से अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को ट्रस्टी न बनाया जाये बल्कि कला संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र के लोगों को ट्रस्टी बनाया जाय । उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वायत्तता किस लिये? किस चीज के लिये स्वायत्तता ? केवल स्वायत्तता के लिये स्वायत्तता, जीने के लिये जीना या इसका और कोई अर्थ भी है । स्वायत्तता का मेरी निगाह में केवल एक अर्थ होता है और वह है रचनात्मक स्वायत्तता । जब तक स्वायत्तता का कोई उद्देश्य नही होता तब तक स्वायत्तता का कोई अर्थ समाज के लिये नहीं होता । उपसभाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के काल में आप जानते हैं कि कितना कठिन प्रशासन था । लेकिन आकाशवाणी का सर्वश्रेष्ठ युग वही रहा क्योंकि वहां उन दिनों बुखारी साहब थे । बुखारी साहब कोई राजनेता नही थे । बल्कि उस मीडियम को, संचार माध्यमों को समझने वाले एक व्यक्ति थे । उन्होंने उसकी सम्भावनाओं को पूरी तरह एक्सप्लाइट किया और आकाशवाणी को इतना विश्वसनीय बना दिया

[The Vice-Chairman (Shri U. K. Lakshmana Gowda) in the Chair]

कि वर्षों तक सर्वश्रेष्ट कलाकार और कवि आकाशवाणी में रहने में गर्व का अनुभव करते थे । सुमित्रा नन्दन पन्त जैसे लोग बाद में उधर आये लेकिन उसी परम्परा में आये । क्योंकि आकाशवाणी एक विश्वसनीय शब्द बन गया था । लेकिन उसके बाद उसमें नौकरशाही आने लगी । आकाशवाणी का संचालन जो लोग करते थे वे इस माध्यम को, संचार माध्यम के रूप में न देखकर केवल एक राजनैतिक माध्यम के रूप में देखने लगे और इससे उसकी विश्वसनीयता खत्म होने लगी और आज उसमें बड़े कलाकार और कवि आना पसन्द नही करते ।

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं टेलीविजन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद यह बीसवीं शताब्दी का सबसे खतरनाक अस्त्र है और सबसे उपयोगी अस्त्र है। क्योंकि टेलीविजन ड्राईंग रूम का एक जरूरी अंग बन गया है और कोई भी ड्राइंग रूम इसके बिना सम्भव नहीं होता। आप जानते हैं कि माध्यम वर्ग के जीवन का ड्राईंग रूम एक अभिन्न अंग है और दूसरे शब्दों में टेलीविजन के बिना उसका जीवन अधूरा है। आप सोचिए कि टेलीविजन क्या कहर बरपा कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ उसकी उपयोगिता भी हो सकती है जिसको हमने देखा भी है। इमरजेंसी की बहुत सी बुराइयां होती हैं लेकिन कुछ चीजों की गणना नहीं होती है वह गणना चाहें तो आप करा सकते हैं कि 1975 और 1976 में फैमिली प्लानिंग के मामले में ग्रामीणों को सबसे अधिक शिक्षित किया टेलीविजन के साइट प्रोग्राम ने, यह उसकी उपयोगिता थी।

महोदय सवाल यह है कि संचार माध्यम का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 साल में एक लड़का जवान हो जाता है लेकिन टेलीविजन को 21 साल से अधिक होने को आया है परन्तु अब भी वह एक अबोध शिशु की तरह व्यवहार कर रहा है। हिन्दुस्तान का टेलीविजन किसी कबाड़खाने में रखने के लायक नहीं है। न तो वह ड्राईंग रूम की शोभा है और न उससे एजूकेशन किसी तरह का हो रहा है। ऐसा क्यों है। क्योंकि संचार माध्यम को नहीं समझा गया है। यह नहीं समझा गया कि टेलीविजन क्या कर सकता है और क्या नहीं? वह शौकीन लोगों के हाथों में पड़ गया है जैसे कि एक मुहावरा है...

एक माननीय सदस्य : ड्राईंग रूम का डैकोरेशन है...

श्री श्रीकान्त वर्मा : जैसे कि एक मुहावरा है कि एक जापानी बच्चे की कब्र पर लिखा हुआ था कि वह तितलियों की तलाश में बहुत दूर निकल गया। मुझे लगता है कि टेलीविजन भी लड़कियों की तलाश में बहुत दूर निकल गया है, सुन्दर लड़कियों की तलाश में। लेकिन टेलीविजन एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता पर आक्रमण हो सकता है, दो सभ्यताओं का एक साक्षात्कार हो सकता है। एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता के साथ मिलन है। वह हम पर निर्भर है कि हम क्या करना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं 2-3 और बातें कहना चाहता हूं और वह यह हैं कि यदि इन संचार के माध्यमों को ठीक से नहीं समझा गया तो इसका कारण यह था कि स्वयं सरकार के पास या समाज के पास कोई स्पष्ट कल्पना नहीं थी।

फिल्डन से मैकलुहन के जमाने के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। फिल्डन की कल्पना और थी और मैकलुहन के लिए मीडियम इज दी मैसेज था। ये टेलीविजन और रेडियो आज खुद अपने आपमें एक मीडियम हो गये हैं और मीडियम ही संदेश हो गया है। यह युग वहां तक पहुंच गया है इसकी कल्पना हमारे पास नहीं है। बेहतर होता यदि हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीटयूट होता एवं हम प्रशिक्षण केन्द्रों में टेलीकास्टरों और ब्राडकास्टरों को ज्यादा बेहतर शिक्षा दे सकते और हमें स्पोकन वर्ड तथा रिटन वर्ड में फर्क नजर आता। अक्सर जब मैं रेडियो सुनता हूं तो मुझे रिटन वर्ड और स्पोकन वर्ड में कोई फर्क नहीं नजर आता है। एक बोला हुआ शब्द, जो मैं शब्द बोलता हूं या आप बोलते हैं उसका असर कुछ और होगा तथा लिखे हुए शब्द का कुछ और होगा। लेकिन रेडियो की स्क्रिप्ट को जब भी मैंने सुना या पढ़ा तो मैंने बोले में और लिखे में कोई फर्क नहीं पाया। क्योंकि स्पोकन वर्ड का कोई कान्सेप्ट अब तक नहीं विकसित हो सका है। कोई प्रशिक्षण केन्द्र इस सम्बन्ध मे नहीं बना है जो इसको सिखा सके। ठीक उसी तरह

टेलीविजन का व्यू या दर्शन या इसकी चित्त कल्पना को कर सकने वाली कोई संस्था हमारे पास नहीं है । पूना फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है लेकिन हम जानते हैं कि वह कितनी दुरावस्था में है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि आपके पास इसकी कल्पना ही न हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका विकास होगा । वर्गीज कमेटी ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें दी हैं जिनको सरकार को मान लेना चाहिए और साथ ही साथ चूंकि आप बहुत कह रहे है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए औरों को भी बोलना है समय तो आपका खत्म हो चुका है. . .

(Interruptions)

श्री मनुभाई मोतीलाल पटेल (गुजरात): बहुत अच्छा बोल रहे हैं. . . .

SHRI SHRIKANT VERMA: You are not used to listening to intelligent talks.

AN HON. MEMBER: We are listening very patiently.

श्री श्रीकान्त वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे आकाशवाणी के या समाचार विभाग के विकास न हो सकने का एक कारण तो मैंने बताया कि उसने विश्वसनीयता खो दी है । दूसरा कारण यह भी बताया कि आकाशवाणी हो या टेलीविजन उनके समाचार विभागों का विकास तभी संभव हो सकता है जबकि बड़े पैमाने पर उनके अपने संवाददाता हों । आकाशवाणी के संवाददाता दूसरे हों तथा टेलीविजन के संवाददाता छाया संवाददाता हों । जब भी मैंने अमरीका या जर्मनी अथवा और देशों में उनके टेलीविजन के कार्यक्रम देखे तो मैं विस्मित रहा कि उनके करेस्पोंडेंट क्या होते हैं । हमारे यहां करेस्पोंडेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है । हमको समाचार एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है और अक्सर आडवाणी जी को उठकर यहां पर कहना पड़ता है कि ये समाचार रेडियो ने दिया क्योंकि इसको 'समाचार' ने भेजा था । मैं चाहता हूं कि यह नौबत बार-बार न आये इसके लिए रेडियो अपने संवाददाता स्वयं रखे । इस समय मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 85 फुल टाईम करेस्पोंडेंट हैं । लेकिन ये 85 फुल टाईम करेस्पोंडेंट क्या हैं यह हम जानते हैं । ये छोटे छोटे शहरों में लोग है, इनको करेस्पोंडेंट नहीं कहा जा सकता है अगर ये करेस्पोंडेंट हैं तो मेरी करेस्पोंडेंट की कल्पना कुछ और है । इसके अलावा लगभग 216 पार्ट टाईम करेस्पोंडेंट भी है । मान लीजिए कि ये सारे के सारे पार्ट टाईम करेस्पोंडेंट फुल टाईम करेस्पोंडेंट हैं तो भी ये कम हैं । क्योंकि देश आकाशवाणी के जाल में आबद्ध हो चुका है और हजारों करेस्पोंडेंटस की तादाद होनी चाहिए । इसका बजट बढ़ाना चाहिए और जिस समय वर्गीज कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया जाये तो उस समय विशेषकर इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसके लिए समाचार संवाददाता अधिक से अधिक रखें जायें । क्योंकि एक और वर्गीज कमेटी की सिफारिशों से नियुक्त संस्था यह चाहेगी कि उसकी विश्वसनीयता बने लेकिन दूसरी ओर उसके हाथ पाव कटे हुए होंगे . . .

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please conclude.

श्री श्रीकान्त वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही वक्त दिया लेकिन मैं आखिर में सरकार से यही कहूंगा कि यदि सरकार वास्तव में यह चाहती है कि एक स्वायत्त निगम या न्यास कायम हो

[श्री श्रीकांत वर्मा]

तो उसको केवल उन्हीं सिफारिशों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो कि सुविधाजनक हों या जो उसे सुविधाजनक लगती है, बल्कि उन सिफारिशों को भी स्वीकार करना चाहिए जो उसे असुविधाजनक लगें क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी सिफारिशें हैं जिनको कि शायद सरकार स्वीकार करना नहीं चाहेगी। मैं चाहता हूं, आज ही आडवाणी जी यह आश्वासन दें कि वे वर्गीज कमेटी की मुख्य सिफारिशों की अवहेलना नहीं करेंगे।

REFERENCE TO ALLEGED DEMOLITIONS IN SUBZI MANDI AREA, DELHI

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): No, no. This discussion is going on.

श्री सीताराम केसरी : बहुत सीरियस बात है। सब्जी मंडी एरिया में मकानात गिराए जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है—पुलिस कर रही है। इस पर सरकार का ध्यान हम अपनी ओर से आकर्षित करना चाहते हैं। जनता सरकार ने जिस आधार पर वोट लिए, अब सरकार में आकर वही काम नहीं कर रहे हैं क्या। उपसभाध्यक्ष जी सारे मकान गिराए जा रहे हैं और लाठी चार्ज हो रहा है।

DISCUSSION UNDER RULE 176

Report of the working group on autonomy for Akashvani and Doordarshan—contd.

DR. SARUP SINGH (Haryana): Sir, I agree with many things that Shri Shrikant Verma has said. In fact I am greatly impressed by quite a few things that he has said. I think the Opposition parties always feel that if the Prime Minister has a hand in nominating anybody or recommending somebody's nomination, perhaps that would be a political decision. However, Mr. Vice-Chairman, Sir, there is a difficulty here. How are some of these people appointed? Take the Chairman of the University Grants Commission, Chairman of the Union Public Service Commission, Judges, Vice-Chancellors of certain Central Universities, etc. I have been giving a lot of thought to this. I personally feel that the appointees must be free as far as possible; they must not be under the pressure of anybody. I hate and resent political pressure. And I can assure Shri Verma that I will not be a partisan at all in a matter like this, because it is a national matter. After all, the All-India Radio and Doordarshan are very sensitive areas, very vital areas of our national life. Firstly, I am of the opinion that in all matters, not merely in the case of All India Radio but in most matters at any rate, it should be possible for us to take non-party decisions.

In a multi-party system, in a plural society, it is absolutely necessary that we rise above politics. I am not a politician myself. I have come to politics very recently and I feel that it is bad politics, unhealthy politics, which invades all aspects of our national life. Unfortunately, some of the fear of Mr. Verma may not be baseless. But then I would like to say this to him, universities were given autonomy and slowly and gradually that autonomy was eroded. Who was responsible for this erosion? I have been Vice-Chancellor myself. I can assure him that it is not the Government alone that erodes the autonomy of an institution. There are so many areas from which the attacks come. They come from, I am sorry to say, Mr. Vice-Chairman, essentially from the political parties in the country. I